भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भावी सुधार

*उर्वशी प्रसाद

विविध शोधों से पता चलता है कि बेहतर स्वास्थ्य परिणाम आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवा के लिए अतिरिक्त निधि सुरक्षित करना और साथ ही, वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी शासन महत्वपूर्ण है, चूंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्राथमिकताओं में बदलाव स्वास्थ्य सेवा पहलों की निरंतरता को बाधित कर सकते हैं। अंततः चुनौतियों पर काबू पाने हेतु एक लचीली और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास ज़रूरी हैं।

भारत ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में 500 मिलियन से अधिक नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान हो गई है। 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAM) की स्थापना ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान को और बेहतर बनाया है।

पिछले दस वर्षों में, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए चिकित्सा शिक्षा सीटों की उपलब्धता दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि वर्ष 2014 में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय 63% से घटकर वर्ष 2024 में 39% हो गया है। इस प्रगति के बावजूद, भारत को अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा देश 2047 तक 'विकसित भारत' होने की आकांक्षा रखता है।

भारत में इस समय औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, जबकि तुलनात्मक दृष्टि से चीन में 77 वर्ष, जापान में 84 वर्ष और ब्राज़ील में 75 वर्ष है। भारत में शिशु मृत्यु दर

*लेखिका उपाध्यक्ष का कार्यालय, नीति आयोग, भारत सरकार में निदेशक रह चुकी हैं।

(IMR) प्रत्येक 1,000 पैदा होने वाले शिशुओं पर 28 की है, जो चीन में प्रति हजार पर मात्र 5 है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण अफ्रीका में आउट-ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च लगभग 8% है, जो भारत के 39% से बिल्कुल अलग है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा सुधारों के कार्यान्वयन में कई बाधाएँ आती हैं। स्वास्थ्य सेवा पहलों के लिए लगातार और पर्याप्त धन प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी माँगों और सीमित संसाधनों के कारण अक्सर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, कई ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी है, जहाँ अस्पतालों, क्लीनिकों और नैदानिक सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण विकास और रखरखाव के लिए व्यापक निवेश और समय की आवश्यकता है। इसके अलावा, जटिल विनियामक ढाँचा और नौकरशाही प्रक्रियाएं समय पर किए जाने वाले सुधारों के क्रियान्वयन में बाधा डाल सकती हैं, जो यह दर्शाता है कि सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की नितांत आवश्यकता है।

नई स्वास्थ्य सेवा पहलों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कम जागरूकता के कारण उपलब्ध सेवाओं का कम उपयोग हो सकता है। हालांकि प्रौद्योगिकी का समावेशन एक फोकल पॉइंट है, परंतु इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। जनसंख्या के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमज़ोर समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी डॉक्टरों, नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों सहित पेशेवरों की बहुत बड़ी कमी से जूझ रहा है, जिससे कुशल कर्मियों का प्रशिक्षण और उन्हें बनाए रखना, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान में, भारत में हर 10,000 लोगों पर 10 डॉक्टर और 17 नर्स और दाइयाँ हैं। इसकी तुलना में, चीन और ब्राज़ील जैसे मध्यम आय वाले देशों में हर 10,000 व्यक्तियों पर 17 डॉक्टर और 40 नर्स और दाइयाँ हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले देशों में हर 10,000 लोगों पर 39 डॉक्टर और 120 नर्स और दाइयाँ हैं।

सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार जनसांख्यिकीय लाभ उठाकर युवाओं को सूचित स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने वाली दूरदर्शी नीतियों को अपनाने के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति हो सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन आवंटित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में कहा गया है कि भारत का स्वास्थ्य सेवा व्यय 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक पहुँच जाना चाहिए।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व्यय में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा अनुसंधान और जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। जबकि कुछ राज्यों ने एनएचपी 2017 द्वारा निर्धारित 8% व्यय लक्ष्य को पार कर लिया है, अन्य पिछड़ गए हैं, जिससे देश भर में स्वास्थ्य सेवा निधि में विसंगतियों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त, पोषण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता में निवेश बढ़ाना बचपन के कुपोषण को दूर करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। संस्थानों और छात्र प्रवेश की संख्या बढ़ाकर चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना एक बड़ा कार्यबल बनाने के लिए आवश्यक है। बेहतर वेतन और नौकरी की सुरक्षा सहित काम करने की स्थितियों में सुधार करना मौजूदा पेशेवरों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में होने वाले अंतराल का समाधान प्रभावी ढंग से हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में कार्यरत भारतीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ कमी को दूर कर सकती हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ा सकता है और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी साझा कर सकता है। टेलीमेडिसिन जैसी तकनीक को अपनाने से मौजूदा पेशेवरों की दक्षता को अनुकूल बनाया जा सकता है। कौशल वृद्धि और प्रतिधारण के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है, जबकि नियामक सुधार नई प्रथाओं और संस्थानों की स्थापना को सरल बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर, भारत अधिक लचीली और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के लिए प्रयास कर सकता है।

बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना भी आवश्यक है, विशेष रूप से 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और शिक्षा पर ज़ोर देना होगा। जीवन के शुरुआती 1000 दिन, जो एक महिला के गर्भधारण से लेकर उसके बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक होते हैं, आजीवन स्वास्थ्य और विकास के लिए आधार तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इस समयावधि के दौरान उचित पोषण और देखभाल न केवल बच्चे के जीवित रहने के लिए बल्कि उनके पनपने, सीखने और गरीबी के चक्र से बाहर निकलने की क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। मौजूदा 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों को मज़बूत करना और कर्मचारियों को बाल विकास और लर्निंग में पर्याप्त प्रशिक्षण से लैस करना महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है।

एक और महत्वपूर्ण विचार स्कूलों में छात्रों का स्वास्थ्य है। स्कूल-आयु अवधि पोषक तत्वों को इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तेजी से विकास में सहायता मिलती है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भारत के लिए अपने युवाओं की क्षमता का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भविष्य के कार्यबल को आकार देने और देश की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने में सहायक होंगे। राष्ट्रव्यापी स्कूल स्वास्थ्य पहल को लागू करने से 6 से 18 वर्ष की आयु के 255 मिलियन स्कूली बच्चों और किशोरों के समग्र कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग, शारीरिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, परामर्श और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने वाला स्कूल वातावरण स्थापित करना एक प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए।

वर्ष 2047 तक इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आधारशिला के रूप में कार्य कर सकती है, जिसमें आयुष्मान अरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से नागरिकों का कल्याण सेवाओं के प्रभावी प्रावधान पर निर्भर करेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए 2027 तक सभी आयुष्मान अरोग्य मंदिर (एएएम) का पूर्ण परिवर्तन अनिवार्य है। 2018 से एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें कम से कम 173,000 एएएम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति सहित अवसंरचनात्मक उन्नति, टेलीमेडिसिन और मुफ्त दवाओं और निदान का वितरण शामिल है।

फिर भी, विभिन्न राज्यों में पूर्ण संचालन, कवरेज, गुणवत्ता और निरंतरता के संबंध में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा पैकेज के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य, तीव्र देखभाल, वृद्धावस्था देखभाल, मौखिक, दृश्य और ईएनटी उपचार घटकों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। अन्य कार्यान्वित घटकों को कुछ एएएम पर दवाओं और निदान की असंगत आपूर्ति के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जाँच शुरू हो गई है, कैंसर की जाँच दरों में सुधार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ उपचार, अनुवर्ती कार्रवाई और अतिरिक्त सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को भी इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जागरूकता और पहुँच की कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों के बीच अतःपात्र व्यक्तियों को AB-PMJAY के

तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए बेहतर संचार रणनीतियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वित्त पोषण और राज्य की भागीदारी भी चुनौतियाँ पेश करती है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी है। कुछ राज्य AB-PMJAY को लागू करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कवरेज असमान है।

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में भी काफी कमियाँ हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जिसके लिए योजना हेतु आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश और समय की आवश्यकता होती है। देखभाल की गुणवत्ता एक चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें अस्पतालों के पैनल, मान्यता और सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए निगरानी से संबंधित चुनौतियाँ समक्ष खड़ी हैं। इसके अलावा, AB-PMJAY के कार्यान्वयन में जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा बाधा उत्पन्न होती है, जो योजना की प्रभावशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए संचालन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता को उजागर करती है। सिस्टम के भीतर धोखाधड़ी और दुरुपयोग जोखिमपूर्ण है, जिससे धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए मज़बूत तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है।

व्यापक कवरेज और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी समन्वय भी आवश्यक है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयास के साथ-साथ निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता है।

स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक

भारत में पोषण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए कई आवश्यक रणनीतियों की आवश्यकता है। प्रगति को ट्रैक करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, तथा इसमें नियमित ऑडिट और फीडबैक तंत्र होने से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा भी मिलता है। पोषण पहलों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से उनकी प्रासंगिकता और स्वीकृति में काफी सुधार हो सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा (ASHA) सहित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण पोषण सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने और लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कुपोषण के जटिल मुद्दे से निपटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। व्यापक जन जागरूकता अभियान लागू करने से आबादी को पोषण के महत्व और सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिससे भागीदारी और अनुपालन में वृद्धि हो सकती है।

डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से सेवा वितरण को अनुकूल बनाया जा सकता है, जिससे प्रगति की निगरानी सुविधाजनक होने के साथ-साथ सूचना का कुशल प्रसार सक्षम हो सकता है। पर्याप्त धन प्राप्त करने, सहायक कानून बनाने और राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए सभी सरकारी स्तरों पर मज़बूत नीति समर्थन और सहयोग आवश्यक है।

पौष्टिक भोजन और पूरक आहार की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति शृंखला चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है जिसमें खरीद, भंडारण और वितरण के रसद लॉजिस्टिकस और प्रबंधन में सुधार करना शामिल है।

अंततः गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों जैसी संवेदनशील आबादी के लिए लक्षित हस्तक्षेप विकसित करना उनकी विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके भारत को अतिरिक्त

संसाधन, विशेषज्ञता और अभिनव समाधान प्रदान किए जा सकते हैं। इन साझेदारियों को प्राथमिकता देकर, देश अपनी पोषण पहलों की प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है और कुपोषण को दूर करने में पर्याप्त प्रगति कर सकता है।

भारत के पेयजल और स्वच्छता क्षेत्रों से संबंधित भावी सुधारों में सभी नागरिकों के लिए स्थायी और समान पहुँच की गारंटी देने के लिए कई आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जल और स्वच्छता सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कार्य निष्पादन बढ़ाना और सिस्टम सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण है, जिसे बेहतर प्रबंधन प्रथाओं, सतत निगरानी और पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सेवा प्रदाताओं द्वारा विस्तृत परिचालन और वित्तीय डेटा का प्रकाशन शामिल है। नवाचार, निवेश और विशेषज्ञता लाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना महत्वपूर्ण है, जिससे एक मज़बूत WASH (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा और जिससे सेवा वितरण और बुनियादी ढाँचे की कमियों का समाधान भी होगा।

जल संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और उपचारित जल के पुनः उपयोग को शामिल करते हुए नियोजन और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत अप्रोच आवश्यक है। जल और स्वच्छता परियोजनाओं की योजना और कार्य निष्पादन में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय भागीदारी इन पहलों की प्रासंगिकता और स्वीकृति को बढ़ाती है। जल गुणवत्ता निगरानी में सुधार, पानी की बर्बादी को कम करने और स्वच्छता सुविधाओं को उन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचारों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें स्मार्ट वॉटर मीटर और आईओटी-आधारित निगरानी प्रणाली जैसे उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जल गुणवत्ता मानकों और स्वच्छता मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नीति और विनियामक ढांचे को मज़बूत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रदूषण के लिए सख्त दंड लगाना और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। अंत में, स्थानीय अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है ताकि वे जल और स्वच्छता सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में अपनी क्षमता बढ़ा सकें, जिससे समग्र सेवा वितरण और रखरखाव में सुधार हो सके।

जलवायु अनुकूलन में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध जल और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाना शामिल है। इसमें गंभीर मौसम स्थितियों को सहन करने और सूखे की अवधि के दौरान पानी की आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम प्रणालियों के डिज़ाइन तैयार करना शामिल है। इन पहलों को प्राथमिकता देकर, भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुँच के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ सकता है।

शोध से पता चलता है कि बेहतर स्वास्थ्य परिणाम आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवा के लिए अतिरिक्त निधि सुरक्षित करना और साथ ही, वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी शासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्राथमिकताओं में बदलाव स्वास्थ्य सेवा पहलों की निरंतरता को बाधित कर सकते हैं। अंततः चुनौतियों पर काबू पाने हेतु एक लचीली और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। ❑